

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का 'सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन': प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन में अंतर के विशेष संदर्भ में

सत्यप्रकाश यादव, (Ph.D.), शिक्षा विभाग,
पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Corresponding Author

सत्यप्रकाश यादव, (Ph.D.), शिक्षा विभाग,
पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 21/06/2022

Revised on : -----

Accepted on : 28/06/2022

Plagiarism : 05% on 21/06/2022



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 5%

Date: Tuesday, June 21, 2022

Statistics: 88 words Plagiarized / 1684 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का 'सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन': प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन में अंतर के विशेष संदर्भ में डॉ. सत्यप्रकाश यादव सहायक प्राध्यापक पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

जैसे उत्तम कार्य में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी हैं। आज उसे जहाँ स्वयं विद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय-विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। वास्तव में अध्यापक ही संस्था द्वारा प्रदत्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध निष्कर्षों के प्रकाश में राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण

संस्थाओं के प्रयोगात्मक कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें अनुभूत समस्याओं के निराकरण के उन्नयन में दिशा-निर्देशन प्राप्त होगा और शिक्षकों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा। इक्कीसवीं शताब्दी का भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उसको इस विकास-पथ पर आगे बढ़ाने हेतु एक कुशल मानव संसाधन के रूप में योग्य नागरिकों की आवश्यकता है।

शोध सार

शिक्षण जैसे उत्तम कार्य में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी हैं। आज उसे जहाँ स्वयं विद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय-विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। वास्तव में अध्यापक ही संस्था द्वारा प्रदत्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध निष्कर्षों के प्रकाश में राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रयोगात्मक कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें अनुभूत समस्याओं के निराकरण के उन्नयन में दिशा-निर्देशन प्राप्त होगा और शिक्षकों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा।

मुख्य शब्द

डी.एल.एड, प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शैक्षिक पुनर्गठन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्.

इक्कीसवीं शताब्दी का भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उसको इस विकास-पथ पर आगे बढ़ाने हेतु एक कुशल मानव संसाधन के रूप में योग्य नागरिकों की आवश्यकता है। उनके इस आवश्यकता की पूर्ति देश की अच्छी शिक्षा-व्यवस्था तथा उन्नत शिक्षक-शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी चुनौतियों का सामना करना संभव हो सकेगा। शिक्षा की दृष्टि से "प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण", "गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा", आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लक्ष्य रहें हैं। इसी क्रम में 6 से 14 वर्ष की आयुसमूह के बच्चों को अनिवार्य व

April to June 2022

www.shodhsamagam.com

A Double-blind, Peer-reviewed, Quarterly, Multidisciplinary and Multilingual Research Journal

Impact Factor
SJIF (2022): 6.679

565

निःशुल्क शिक्षा देना, आज उनका मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही यह लक्ष्य देश का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी हो गया है। व्यवहारिक रूप से देश के शैक्षिक समस्याओं की जांच करने वाले प्रत्येक शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की दशा की ओर विशिष्ट ध्यान दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने भी कहा है कि हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आमूलचूल शैक्षिक पुनर्गठन में अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार शिक्षा की विशिष्टता तथा गुण को प्रभावित करने वाले एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी विभिन्न घटकों में निःसंदेह रूप से शिक्षकों की योग्यता एवं उनके गुण सर्वाधिक प्रभावकारी हैं। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

छत्तीसगढ़ में शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छत्तीसगढ़, 2018 के आकड़ों के अनुसार 27 जिलों में कुल 21 शासकीय एवं 68 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित हो रही हैं जिनमें दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारंभिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 28 नवंबर 2014 जिसका प्रकाशन भारत राजपत्र (भाग-3 खण्ड चार) के पृष्ठ 13 परिशिष्ट-2 में अंकित प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्चा के मानदंड और मानकों में दिए गये विभिन्न मुद्दों यथा इण्टर्नशिप को गुणवत्ता सूचकांक मानकर (Quality Indicators) शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएं का सम्पूर्ण गुणवत्ता का मापन किया गया है। प्रस्तुत शोध में सम्पूर्ण गुणवत्ता मापन/मूल्यांकन का यही अभिप्राय है।

अध्ययन का औचित्य

आज के युग में क्षमतावान शिक्षकों की महती आवश्यकता है, विशेषकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के विषय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वर्तमान में पूरे शिक्षा जगत का ध्यान प्रारंभिक शिक्षकों की ओर आकृष्ट हो रहा है। लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर बिलासपुर गुरुवार 9 नवंबर, 2017 के पृष्ठ 18 पर मुद्रित समाचार के अनुसार "शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मार्च 2019 के पहले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. यानी डिप्लोमा इन इलिमेंट्री एजुकेशन का दो साल का कोर्स करना होगा। केन्द्र सरकार ने चाहे वह निजी हो, या फिर शासकीय या अर्द्धशासकीय या अनुदान प्राप्त, सभी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्स न करने पर शिक्षक अध्यापनकार्य से वंचित हो जायेंगे और उनके सामने रोजी-रोटी का प्रश्न खड़ा हो जायेगा।" इस समाचार के अनुसार डाईट एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का महत्व प्रारंभिक शिक्षा जगत में अचानक बढ़ गया है इसलिए डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं ने प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति को सकारात्मक बना दिये हैं। ऐसे सभी वे उम्मीदवार जो इस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सुविधा संपन्न प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर अध्यापक बनने की पात्रता पा लेना चाहते हैं। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रारंभ में प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति, प्रशिक्षण पूरा करने पर प्राप्त अभिवृत्ति में परिवर्तन आना, प्रशिक्षण के प्रति अत्यंत सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास का संकेत देता है और सुविधा संपन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता निरूपित करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता व सार्थकता उपरोक्त गद्यांशों के प्रकाश में रेखांकित होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में किए गए प्रयोगात्मक कार्य की तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना

H₁ शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन में अंतर होता है।

शोध प्रकल्प

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक अध्ययन है जिसमें सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

शोध न्यादर्श

छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में 21 शासकीय डी.एल.एड. एवं 68 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ वर्तमान में संचालित हैं। अध्ययन हेतु 09 शासकीय एवं 09 अशासकीय संस्थाओं को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया द्वारा चुना गया है, जिसके तहत जिस जिले में शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं। उन्हीं जिलों की अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाएँ न्यादर्श में शामिल है, तथा प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रथम वर्ष से 25 एवं द्वितीय वर्ष से 25 प्रशिक्षार्थी, 07 शिक्षक-प्रशिक्षक एवं 01 प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष को प्रश्नावली भरने हेतु चयन किया गया।

शोध चरांक

प्रस्तुत अध्ययन में चर एवं उनके स्तर निम्नानुसार है:

स्वतंत्र चर

- डाईट/डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक के अनुपालन के स्तर।
- संस्थाओं के प्रकार: शासकीय एवं अशासकीय।

आश्रित चर

डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन इस अध्ययन के आश्रित चर है।

अध्ययन में प्रयुक्त शोध उपकरण

शैक्षिक गुणवत्ता मापनी प्रश्नावली-शैक्षिक गुणवत्ता मापनी प्रश्नावली का निर्माण शोध-निर्देशक एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों एवं मानकीकृत दिशानिर्देशों के आधार पर शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया गया है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण एवं व्याख्या

H₁ शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन में अंतर होता है।

उपरोक्त परिकल्पना के परीक्षण हेतु 't' की गणना निम्नांकित सारणी के अनुसार प्राप्त हुई है:

प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षार्थी एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के मत संबंधी परीक्षण परिणाम

चरांक	संस्थाएं	N	M	SD	't'	व्याख्या
प्रयोगात्मक कार्य का क्रियान्वयन	शासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	487	8.57	1.23	1.013*	P>.05
	अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	513	8.65	1.38		

*Not significant

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

निष्कर्ष

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय प्रशिक्षण संस्था का मध्यमान 8.57 है, जबकि अशासकीय संस्था का मध्यमान 8.65 है गणना से प्राप्त 't' का मान (1.013) .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर प्राप्त सारणीगत मान से कम है, अतः शोध परिकल्पना H₁ अस्वीकृत होती है। इस तरह स्पष्ट है कि शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन में अंतर नहीं होता है।

विवेचना

निष्कर्ष की विवेचना करने पर स्पष्ट होता है कि शासकीय एवं अशासकीय दोनों ही डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगात्मक कार्य जैसे शिल्प कला, ललित कला, शिक्षा में सृजनात्मक नाटक, आत्म विकास, बच्चों के शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य, शिक्षा में व्यवसायिक कौशलों और योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करना जैसी अलग-अलग गतिविधियां की जाती है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षार्थियों का संवागीण विकास हो सके। अतः इनके क्रियान्वयन में संस्थाओं के प्रकार के आधार पर अंतर नहीं पाया गया है। किन्तु मोहन (1980) एवं शर्मा (1988) के द्वारा दिये गये निष्कर्ष इसके विपरीत पाए गए हैं, इनके अनुसार शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थाओं में क्रियात्मक कार्य बहुत कम कराये जाते हैं और जो कार्य कराये जाते हैं वो भी परंपरागत तकनीक से कराये जाते हैं। उपयुक्त अध्ययन पुराना है, वर्तमान में डाईट्स व डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षकों को इन पाठ्यक्रमों में क्रियान्वयन संबंधी प्रशिक्षण दिये जा रहें हैं, अतः स्थितियों में सुधार हो रहा है इसलिए शिक्षक-प्रशिक्षक व प्रशिक्षार्थियों का प्रयोगात्मक कार्य के क्रियान्वयन के प्रति सार्थक अंतर नहीं होना उचित जान पड़ता है।

सुझाव

राज्य के शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं मानक के अनुकूल बनाने की दृष्टि से उनकी सुविधाओं, विशेषताओं एवं कमजोरियों को उजागर करने संबंधी अध्ययन की विशेष महत्ता है। इससे शिक्षाविदों और शिक्षा अधिकारियों व शासन को अपनी योजना एवं नीति सृष्टि करने में सहायता मिलेगी, साथ ही राज्य में संचालित अन्य सभी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की सुविधाओं को अधुनातन बनाने में सहायता मिलेगी। राज्य में शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों हेतु (सेवापूर्व, सेवाकालीन तथा अल्पकालीन) प्रशिक्षण आयोजित कर राज्य में कुशल शिक्षक तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी। प्रोफेसर सत्यभूषण (2004) के विचारों के अनुकूल राज्य की डाईट्स के संबंध में व्यक्तिगत नीतियों, निकाय के कर्मचारियों के क्षमता-विकास, प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों के विकेंद्रीकरण, प्रशिक्षण संस्थाओं में परस्पर संवाद के अवसर तथा डाईट्स में नवाचारी कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता मिलेगी। प्रस्तुत शोध निष्कर्षों के प्रकाश में राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम एवं क्रियाकलापों के उन्नयन में दिशा-निर्देशन प्राप्त होगा और उन्हें उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. चन्द्रशेखर, के. (2000), एन इवेल्यूवेटिव स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन आन्ध्र प्रदेश, पी-एच.डी. थिसिस-एजुकेशन, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति.
2. चन्द्रशेखर, के. (2017), "टीचर एजुकेशन परसेप्शन ऑफ डाईट्स फेसिलिटीज एण्ड दियर रिलेसन्स टू सर्टन पर्सनल एण्ड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स" पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, बड़ौदा, वाल्यूम 23(2), पृष्ठ 92-104.
3. दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, बिलासपुर, गुरुवार 9 नवंबर, 2017 पृष्ठ 18.
4. दास, आर.सी. एवं जंगीरा, एन.के. (2004), 'ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर एजुकेशन', थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन

एजुकेशन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, पृष्ठ 782-789.

5. डेलर्स, जे. एवं अन्य (1998), "क्वालिटी टीचर्स, लर्निंग: दी ट्रेजर विदिन' रिपोर्ट टु यूनेस्को ऑफ दी इण्टरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, पेरिस, यूनेस्को, कोटेड बाई इन दी इण्डियन्स जर्नल फॉर टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वाल्यूम 1(1), 146..
6. दीपा, कृष्णा एवं सरोज, आनन्द (2006), गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका, अन्वेषिका 3(2), 75-80.
7. मुखोपाध्याय, मारमर (2009), शिक्षा में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन, डायमण्ड पॉकेट बुक (प्रा.) लि., नई दिल्ली
